राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उतरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

सुरत–गुजरात, संस्करण शुक्रवार,15मई2020 वर्ष–2, अंक –72 पृष्ठ–04 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका में दुबारा अर्थव्यवस्था खुलने से विशेषज्ञों की टेंशन बढ़ी

वाशिंगटन (ईएमएस)। कोरोना का केंद्र बने अमेरिका में दोबारा अर्थव्यवस्था खुलने से विशेषज्ञों की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के कई राज्यों में अर्थव्यवस्था खोलने को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसके कारण कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। विशेषज्ञों का मामना है कि पूरे देश में कोविड–19 संक्रमण की स्थिति अलग–अलग है। कुछ स्थानों पर मामले बढ़ रहे हैं तो कुछ स्थानों पर मामले घट रहे हैं। इसके अलावा संक्रमण नाटकीय रूप से कई स्थानों पर इधर–उधर हो सकता है।

जानकारों ने कहा,चुनौती यह है कि हमारा ध्यान राष्ट्रीय आंकड़ों पर केंद्रित है जबकि हम यह देख रहे हैं कि 50 विभिन्न स्थानों पर 50 अलग–अलग आंकड़ें हैं। कुछ राज्यों ने दो सप्ताह बाद ही बंद में रियायत देना शुरू कर दिया था। टेक्सास में शॉपिग मॉल खुलने शुरू हो गए, दक्षिण कैरोलाइना में समुद्र तट पर स्थित होटलों को खोला गया और वायोमिंग में जिम तक खोल दिए गए। जॉर्जिया देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां कुछ कारोबारों के दरवाजे खोले गए। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि कोविड–19 महामारी धीरे–धीरे शुरू होती है और यह कुछ समय अपना पांव जमाने में लेती है और फिर प्रत्यक्ष तौर पर इसका असर दिखने लगता है। इसी बीच जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने आगाह किया है कि हो सकता है कि नया कोरोना वायरस यहां रहने के लिए आया है।

चीन में कोविड–19 के 15 नए मामले

वुहान में 1.1 करोड़ लोगों की जांच शुरू

बीजिंग (ईएमएस)। चीन में गुरुवार को कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए जिनमें से 12 मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं दिखे। वैश्विक महामारी का दूसरा दौर शुरू होने की आशंकाओं के बीच इस जानलेवा संक्रामक रोग का केंद्र रहे वुहान शहर में 1.1 करोड़ लोगों की कोविड–19 के लिए बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने बताया कि तीन मामले स्थानीय हैं जिनमें से दो लियाओनिंग प्रांत और एक जिलिन प्रांत में सामने आया। बुधवार तक चीन मुख्य भूभाग पर संक्रमितों की संख्या 82,929 थी जिनमें से 101 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। चीन में अब तक कुल 4,633 लोग इस संक्रामक रोग के चलते जान गंवा चुके हैं। मामले बढ़ने के बाद जिलिन शहर के अधिकारियों ने कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। जिलिन की उप महापौर गाई डोंगपिंग ने बताया कि शहर में स्थानीय रूप से संक्रमण के 21 मामले सामने आए हैं जिनमें से दो मरीजों को बीमारी के लक्षण नहीं थे। मौजूदा स्थिति बहुत गंभीर और जटिल है तथा इससे संक्रमण के और फैलने का खतरा है। इस महामारी को रोकने के लिए जिलिन महामारी रोकथाम एवं नियंत्रण समूह ने जिलिन के शहरी इलाके में रोकथाम संबंधी कदमों को लागू करने का फैसला किया है।

पाक सेना ने बढ़ाई इमरान की दिक्कत

इस्लामाबाद (ईएमएस)। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई को रिलीफ पैकेज देने के लिए पाकिस्तान के पास पर्याप्त बजट नहीं है। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने सैलरी बढ़ाने की मांग की है। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 35,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पाक सेना ने मांग की है कि 2020–21 के लिए उनकी सैलरी 20 फीसदी बढ़ाई जाए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर ऐसा किया जाता है तो राजकोष को 6,367 करोड़ का झटका लग सकता है। मंत्रालय को दिए गए ज्ञापन में दावा किया गया है कि सेना की सैलरी कम है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। ज्ञापन में कहा गया है कि 2019–20 में ब्रिगेडियर की रैंक तक 5 फीसदी सैलरी बढ़ाई गई थी लेकिन जनरल ऑफिसरों को कोई बढ़त नहीं दी गई थी।

आर्थिक संकट से जूझ रहा पाक

यह मांग ऐसे वक्त में की गई है जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आशंका जताई है कि वैश्विक मंदी का पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान का निर्यात 40 फीसदी तक घट गया है। देश में लगाए गए लॉकडाउन में भी आर्थिक संकट की वजह से ढील दी जा रही है। पाक में अब तक 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 761 लोगों की मौत हो चुकी है।

ब्रिटेन में 7 लाख लोगों की हो सकती है मौत

ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा

लंदन (ईएमएस)। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि महामारी के कारण हजारों और लोगों की जान जा सकती हैं। अध्ययन में कहा गया है कि अगर महामारी पर काबू नहीं पाया गया, तो इस साल के अंत तक ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या एक लाख तक हो सकती है। उधर, एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस और इसके लिए लॉकडाउन जैसे उठाए गए कदमों के कारण ब्रिटेन में सात लाख लोगों की मौत हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के अध्ययन के अनुसार ब्रिटेन में सात लाख लोग इस जानलेवा वायरस से जान गंवा सकते हैं। यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध में हुई मौतों से भी ज्यादा है।

अध्ययन में कहा गया है कि मंदी, गरीबी और लापरवाही की स्थिति में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बिना वैक्सीन के ब्रिटेन को कोविड–19 को हराने के लिए 2024 तक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मंदी भी आ सकती है। ऐसे में कोरोना वायरस, खराब स्वास्थ्य प्रणाली और गरीबी की वजह से पांच साल में 6.75 लाख लोगों की मौत हो सकती है।

श्रम कानून में हुए बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली(ईएमएस)। विदेशी निवेशकों को भारत लाने के मकसद से श्रम कानून में हुए बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की गयी है। झारखंड के सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उत्तरप्रदेश ,मध्यप्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में श्रमिकों के कानून को कमजोर और शिथिल बनाने का अध्यादेश जारी हुआ है। श्रम कानून में संशोधन तीन महीने से लेकर तीन वर्षों तक के लिए अलग अलग राज्यों में किया गया है।

याचिकाकर्ता पंकज यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकारों के इन अध्यादेशों को रद्द कर श्रम कानून को संरक्षित करें। राज्य सरकारों ने फैक्ट्री एक्ट का संशोधन कर मजदूरों के मूल अधिकारों को हनन करने का प्रयास किया है। आठ घंटे की जगह बारह घंटे कार्य करवाना तथा निम्नतम मजदूरी से भी वंचित रखना मानवाधिकार का हनन है। राज्य सरकारों ने श्रम कानून में बदलाव वॉर के दौरान मिलने वाले राज्य सरकार के अधिकारों के आधार पर किया है जो ना तो राजनीतिक दृष्टि से सही है ना ही नैतिक दृष्टि से। लाखों मजदूर अभी बेइंतहा पीड़ा को झेल रहे हैं और लॉकडाउन के बाद जब वे वापस फैक्ट्री में जाएंगे तो नया अध्यादेश उन्हें अपने फंसे हुए पैसे को निकालने में भी बड़ी अड़चन खड़ा करेगा। यह मजदूरों को देश की आज़ादी से पहले से मिलते आ रहे हर वो अधिकार और सुविधा से वंचित करने की कोशिश है जिसके वे हक़दार हैं। मजदूर की जान की कीमत पर निवेशकों को आमंत्रित करना कहीं से भी उचित नहीं है।

ज्ञात रहे कि भाजपा शासित राज्यों एमपी, गुजरात और उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण कानूनों में संशोधन किया गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और गुजरात ने विभिन्न कल्याणकारी कानूनों के प्रावधानों से औद्योगिक इकाइयों को छूट दी है। इन छूटों में दैनिक और साप्ताहिक कामकाजी घंटों की तरह वृद्धि शामिल है। साथ ही श्रमिकों के अदालत में जाने पर रोक लगाई गई है। निरीक्षकों द्वारा कारखानों के नियमित निरीक्षण का निलंबन किया गया है।

दिल्ली एयरपोर्ट से यूपी रोडवेज शुरू करेगी परिवहन सेवाएं

बस का 1,000 तो टैक्सी का 10,000 रुपए तक हो सकता है किराया

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोनाकाल में लॉकडाउन के चलते देश में यातायात सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। ऐसे समय दूसरे देशों से स्वदेश वापसी करने वाले लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं। जिस पर ध्यान देते हुए यूपी रोडवेज ने एक खाका तैयार किया है। जिसके मुताबिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) से नोएडा और गाजियाबाद के निवासियों को परिवहन की सुविधा दिए जाने पर विचार चल रहा है।

इस संबध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) नोएडा के क्षेत्रीय प्रबंधकों को 9 मई के दिन एक पत्र भेजा गया था। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम होंडा सियाज के लिए 10,000 रुपए और इनोवा के लिए 12,000 रुपए का चार्ज लेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट से घर जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने की बात की गई। जिसका किराया 1,000 हजार रुपए तय किए जाने की बात हो रही है। ज्ञात हो कि 10,000 से 12,000 रुपए अदा कर यात्री कैब की सुविधा ले सकेंगे लेकिन इस कैब में चालक के साथ सिर्फ 2 और यात्री सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठ सकते हैं। जबकि बस में 26 यात्रियों को ही बैठाने की बात हो रही है। पत्र में टैक्सी सर्विस के लिए जो किराया तय करने की बात की गई है। वह महज दिल्ली हवाई अड्डे से 250 किमी तक की दूरी के लिए है। हालांकि इससे ज्यादा का सफर होने पर यात्रियों को क्रमशः दो टैक्सी वेरिएंट में प्रत्येक किमी के लिए 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा।

आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से यात्रियों को नॉनएसी बस के लिए 100 किमी तक की दूरी पर 1,000 रुपए जबकि एसी बस के लिए 1,320 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं, अगले 100 किमी के लिए दोगुना किराया वसूलने की भी बात पत्र में लिखी गई है। निगम के प्रबंध संचालक राज शेखर ने पत्र में कहा कि उन्हें आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से नोएडा एवं गाजियाबाद के यात्रियों के लिए आवश्यक यात्रा की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस सुविधा का लाभ वही यात्री उठा सकते हैं जिनके पास दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा। जिसमें इस बात की सत्यता हो कि उनमें कोविड–19 के लक्षण नहीं हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से विदेशों से भारतीयों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया था। वर्तमान में इन लोगों को दिल्ली में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा गया है।

20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिए बधाई, पर मेरा पूरा कर्ज वापस ले सरकार: विजय माल्या

नई दिल्ली (ईएमएस)। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को एक ट्वीट सरकार से 100 प्रतिशत कर्ज चुकाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सरकार से उनके खिलाफ मामले बंद करने की अपील भी की। माल्या ने हाल में घोषित 20 लाख करोड़ रु के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई देते हुए अफसोस जताया कि उनके बकाया चुकाने के प्रस्तावों को बार–बार नजरअंदाज किया गया।

उन्होंने ट्वीट किया, ''कोविड–19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई। वे जितना चाहें उतने नोट छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की अनदेखी करनी चाहिए, जो सरकार के स्वामित्व वाले बैंक से लिया गया 100: कर्ज वापस करना चाहता है। माल्या बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रवर्तक हैं, और 9,000 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में उनकी तलाश है। उन्होंने कहा कि कृपया बिना किसी शर्त मुझसे धन लीजिए और (मामले को) बंद कीजिए। इस महीने की शुरुआत में माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के लिए लंदन हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हर महीने किसी साथी के पांच वीकऑफ आएंगे और कंपनी की तरह से सिर्फ चार वीक ऑफ मिल रहे हैं। इसलिए जिन साथियों को पांचवां वीकऑफ आएगा वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। ध्यान रहे सिर्फ 5वां वीकऑफ ही।

गौरतलब है कि पिछले महीने ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने माल्या की अपील को खारिज कर दिया था। माल्या ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि निचली अदालत ने गलत तरीके से उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी जबकि साजिश के तहत उनके खिलाफ धोखाधड़ी और

धनशोधन का मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद माल्या ने अपने बारे में मीडिया में कही जा रही बातों पर भी निराशा व्यक्त की थी।

उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया में कही जा रही बातों से भी निराश हूं, जिसके मुताबिक मुझे 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए भारत में मुकदमे का सामना करना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि मेरे और अन्य के खिलाफ आरोप केवल 2009 में आईडीबीआई बैंक से कुल 900 करोड़ रुपये के उधार की तीन किस्तों से संबंधित हैं। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में हैं और अप्रैल 2017 से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर हैं।

माल्या के प्रत्यर्पण का मामला उनके और उनकी कंपनी को द्वारा आईडीबीआई को ठगे जाने पर स्थिर है। 2009 में आईडीबीआई से किंगफिशर एयरलाइन के लिए माल्या ने कई करोड़ रुपये लिए थे। माल्या की दलील है कि उसने व्यापार में नुकसान के चलते बैंक का पैसा नहीं लौटाया था न कि ठगने के इरादे से।

दिल्ली सरकार ने बढ़ाई टेस्ट स्पीड, अब कोरोना के टेस्ट हुए डबल

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 हजार के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 472 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे अधिक हैं। इतने मामले 24 घंटे में अब तक नहीं आए थे।

ऐसे में दिल्ली के लिए मई कोरोना मामलों के लिहाज से सबसे अधिक उछाल वाला महीना साबित हो रहा है। हालांकि इस महीन में कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ी है।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए आंकड़ों को जोड़ा जाए तो दिल्ली में महज मई में 4955 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, दिल्ली में डबलिंग रेट 11 दिन है यानि दिल्ली में कोरोना के केस 11 दिन में डबल हो रहे हैं। अप्रैल के अंत तक डबलिंग रेट 13 दिन था। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की स्पीड काफी तेज हुई है। दिल्ली में सरकार द्वारा जारी मई महीने के आंकड़े के अनुसार 2 मई तक कोरोना के 58210 टेस्ट हुए, जबकि 14 मई 2020 तक दिल्ली में टेस्ट की संख्या 119736 तक पहुंच गई, जोकि 2 मई 2020 के मुकाबले डबल से अधिक है।

बता दें कि 7 मई 2020 को जारी एक आदेश में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए प्राइवेट टेस्टिंग लैब की संख्या 8 से बढ़ाकर 13 कर दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि अगर सरकारी लैब की क्षमता से ज्यादा सैंपल टेस्ट कराने की स्थिति बनती है तो अस्पताल या अथॉरिटी अपने जिले के हिसाब से निर्धारित प्राइवेट लैब को सैंपल टेस्ट कराने भेजेंगे।

ममता ने ट्वीट कर बताया, अलग–अलग हिस्सों में फंसे बंगालियों को लाने जल्द चलेंगी 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन

कोलकाता (ईएमएस)। कोरोना संकट के बीच देश के अलग–अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग–अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलवाने का फैसला लिया गया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बंगाल के जो लोग देश के अलग–अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं,उन्हें वापस लाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी की गई है। इसके अलिए 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें दी जा रही हैं। ममता के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनें देश के अलग–अलग हिस्सों से बंगाल के लिए चलेंगी। ट्रेन कहां से और कब चलेगी, इसकी जानकारी भी ममता ने अपने ट्वीट में दी।

गौरतलब है कि बीते दिनों बंगाल के फंसे हुए लोगों के लिए काफी राजनीति हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले पर ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी।शाह ने ममता को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा था, दूसरे राज्य में मौजूद बंगाल के मजदूर अपने राज्य आना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है। लोगों को अपने यहां लाने में बंगाल सरकार तत्परता नहीं दिखा रही और राज्य में ट्रेनों को प्रवेश करने की मंजूरी नहीं दे रही है। इस चिट्ठी को लेकर राजनीतिक बवाल मचा था और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में इस मसले को उठाया था।

शराब तस्करी के मामले में कांग्रेस विधायक सहित 7 पर केस दर्ज

पटना (ईएमएस)। कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना की गाड़ी से शराब बरामद होने के मामले में बक्सर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने विधायक मुन्ना तिवारी सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बक्सर पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी ही अन्य आरोपियों को भी बक्सर पुलिस गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। हालांकि, अभी विधायक मुन्ना की गिरफ्तारी को लेकर कोई सूचना नहीं है।

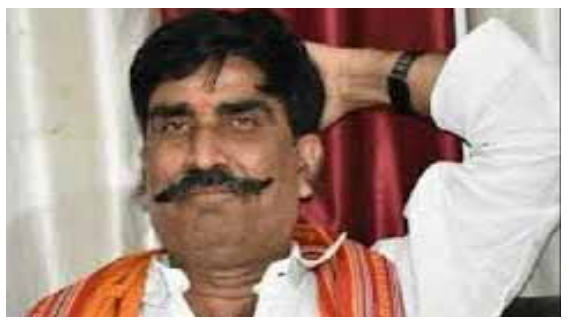

गौरतलब है कि बक्सर में उस समय सनसनीखेज मामला हो गया, जब सेमरी थाने अंतर्गत सदर विधायक मुन्ना तिवारी की गाड़ी शराब की तस्करी करते पकड़ी गई। गाड़ी से आठ बोतल विदेशी शराब के साथ चार लोग को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में बक्सर पुलिस कप्तान ने कहा था कि पकड़ी गई गाड़ी कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी की है। वहीं, विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा था कि गाड़ी मेरी ही है और वहां राहत सामग्री बांटने गई थी। उन्होंने शराब तस्करी के आरोप को खारिज कर दिया था। बहरहाल शराब की तस्करी ने मामले को एक नई मोड़ दे दिया है। अब विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

कोरोना निजीकरण का बहाना न बने

हम और आप सभी मध्यमवगबय लोगों ने कभी ना कभी सुबह सब्जी बेचने वालों की आवाज सुनी होगी और देखा भी होगा। कोरोना के कारण शुरू हुए लॉक डाउन के 15 –20 दिन के बाद एक नया परिवर्तन इसमें दिख रहा है जो कई बातों का संकेत है। पहले सब्जी बेचने वाले ठेले पर निकलते थे और अमूमन उनकी उम्र सीमा 20 वर्ष के ऊपर होती थी। परंतु लॉक डाउन का एक प्रभाव यह हुआ है कि सात आठ वर्ष के बच्चे भी दो–तीन इकट्ठे होकर हाथ ठेला खपचकर सब्जी बेच रहे हैं। और कुछ ज्यादा उम्र वाले लोग साइकिलों पर थेलों पर सब्जी भरकर सब्जी बेच रहे हैं ।तथा पहले जहां सब्जी के ठेले वाले सुबह शाम निकलते थे अब लगभग सारा दिन सब्जी वालों का तांता लगा रहता है। थोड़ी बारीकी से पता करने पर मालूम पड़ा कि यह लोग स्थाई सब्जी बेचने वाले नहप हैं बल्कि जिन के धंधे लाक डाउन में बंद हो चुके हैं घर पर खाने की व्यवस्था नहप है वे या उनके बच्चे लाचार होकर सब्जी बेचने को निकले हैं ।माता–पिता ने बच्चों को भी जो उनकी पढ़ने की उम्र थी उनको पेट की लाचारी में काम में लगाया है। और पूंजी के अभाव में कोई एक खास किस्म की सब्जी उधार में लेकर बेचने निकल रहे हैं ।जिस प्रकार पहले रेलवे प्लेटफार्म पर बच्चे अखबार या अन्य सामान ठेकेदारों से लेकर बेचते थे कि जो बिक गए वह ठीक बकाया वापस कर दिया ।यही स्थिति इस समय इन सब्जी बेचने वालों के रूप में बच्चों की नजर आ रही है ।एक तरफ यह स्थिति सुधरती नजर नहप आती । 2 दिन का लोकडाउन और बढ़ा दिया है तथा जो रियायतें दी जा रही हैं वे भी अभी तक बड़े लोगों के लिए कारखाने दारों के लिए हैं परंतु गरीब या सामान्य वर्ग के लिए नहप है। चाय वाले, पान वाले, सैलून वाले, कोचिंग वाले, जिम वाले और ऐसे ही लाखों उन लोगों के लिए जिन्हें रोज कमाते हैं रोज खाना हैं और जिनका धंधा भी आम गरीबों के भरोसे चलता है । उनके लिए कोई रियायत नजर नहप आती ।बाल श्रमिक कानून पहले भी प्रभावी नहप था परंतु अब तो पूर्णतः अप्रभावी हो गया है ।मानवीय उदारता की सीमाएं भी अब सिकुड़ रही है। पानी पिलाने वाले कुओं का स्रोत स्वतः सूख गया है।

कुछ बड़ी संस्थाएं कुछ सरकारी प्रयास भले ही चलते रहें परंतु आम आदमी के मन की मानवता की धारा अर्थ अभाव में सूखने लगी है ।मेरे पड़ोस में एक नौजवान एक जिम चला कर अपना परिवार चला रहा था । 50–100 बच्चे उसके यहां जिम के लिए आते थे, रोजी रोटी चल रही थी ।कल उसने मेरे सहयोगी धर्मेंद्र राणा को बताया कि अपनी क्षमता भर 20 से 25 दिन मैंने अपने आसपास के गरीबों और लाचारों को अपनी तरफ से खाना खिलाया परंतु अब मेरी क्षमता खत्म हो चुकी है। अब तो मेरे ही खाने के लाले पड़े हैं ।मैं दूसरों को क्या खिलाऊंगा ।यह एक व्यक्ति की पीड़ा नहप है बल्कि लाखों अल्पपूंजी वाले स्वरोजगार बालों की पीड़ा है। आज तो भरी दुपहरी में एक बुजुर्ग महिला पापड़ बेच रही थी ।उनका बेटा भोपाल में पढ़ता है उसके पास आई थी और लॉकडाउन हो गया ।यही बंद हो गई। पैसे खत्म हो गए तो पड़ोसी दुकानदार से पापड़ लेकर बेचने लगी ताकि कुछ पैसे मिल जाएं व खाना चल पाए। भारत सरकार के या राज्य सरकारों के पैकेज में अभी तक इन लोगों के लिए पैकेज पढ़ने और सुनने में नहप आया।

प्रधानमंत्री स्तर पर या सरकारी स्तर पर जब भी चर्चा होती है तो बड़े उद्योग जगत के लिए क्या रियायते मिले इस तक सीमित रहती हैं या थोड़ी बहुत उन बिल्कुल ही गरीब लोगों तक जिन्हें 1000 या 500 की पेंशन में गुजारा करना पड़ता था। उनकी दो–तीन माह की सामाजिक पेंशन की 1000 या 1500 की राशि अगर उनके खातों में पहुंच जाए तो वक्ती तसल्ली हो सकती है परंतु यह हल नहप है ।और तो छोड़िए देश के 1 से 2 करोड़ भिखारी जिनके ना कोई खाते हैं अपवाद छोड़कर ना कोई अन्य रोजगार हैं उन्हें सरकार कैसे मदद पहुंचाएंगी। एक नौजवान जो कुछ दिनों पहले तक चाय का ठेला लगाता था दिन भर में 200 से 300 कमा लेता था अब बेरोजगार है ।पिछले दिनों मालूम चला कि उसने देसी शराब गुटखा बेचना शुरू कर दिया

वहप पेट भरने का जरिया बचा है ।उससे पूछा कि तुम यह क्यों करते हो तो उसने कहा कि एक चाय वाले ने दूसरे चायवाले का धंधा ही बंद करा दिया और क्या करूं।

लॉकडाउन के प्रभाव आने वाले एक डेढ़ वर्ष तक देश के सामान्य व्यक्ति को व्यवस्थित नहप होने देगा ।लाखों महिलाएं जो शादी विवाह में सिर पर हांडा रखकर अपना परिवार चलाती थी शादी घरों और टेंट हाउसों के कामवाले आज भूखमरी के शिकार है। इस मौसम में लाखों मजदूर तेंदूपत्ता व वनोपज संग्रह कर अपना पेट भरते थे अब भूखमरी की गोद में जाने वाले हैं।पत्ता तो खराब होगा ही पत्ता ठेकेदार भी कर्ज में डूब रहे हैं। दिल्ली की सरकारों ने कहने को मनरेगा के काम के नाम पर कुछ राशियां भेजी हैं परंतु वे ऊंट के मुंह में जीरा के समान हैं। छ.ग. से लगभग तेरह लाख लोग धान तैयार होने के बाद यानी लगभग दिसंबर माह से काम के लिए बाहर महानगरों में जाते थे। वे चार या पांच माह बाद मजदूरी कर वापस बारिश के पहले लौटते थे ।क्योंकि वह धान की बुआई का समय होता है।अब लगभग 2 माह से बड़े–बड़े महानगरों में कैद हैं। जनवरी–फरवरी में जो कमाया था वह इस दो माह में घर में बैठ कर खा लिया। अब वापस आने को भी पैसा नहप है ।भारत सरकार ने बड़ी लाचारी में 1 मई को कुछ विशेष मजदूर रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। लाचारी में इसलिए कह रहा हूं कि 29 अप्रैल को देश के गृहमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि रेल गाड़ियां नहप चलेंगी बसों से ले आए। परंतु जब 30 तारीख को देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और यहां तक कि बिहार के भाजपा के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बसों से लाने में तो कई माह लग जाएंगे रेलगाड़ी ही रास्ता है तब इस विरोध को समझ कर आगामी बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर गृह मंत्री जी ने पलटी मारी की विशेष मजदूर रेलगाड़ियां नॉनस्टॉप चलाई जाएंगी। हालांकि यह मांग मैं पिछले 40 दिन से सोशल मीडिया, लेखों, टीबी चेनल व अन्य माध्यमों से कर रहा था। इसमें भी उन्होंने अभी तक निष्पक्षता नहप बरती है और दलीय और एनडीए के चश्मे से रेलों को चलाने का निर्णय कर रहे हैं।आने वाले लोगों से राज्य सरकारें किराया भी ले रही है साथ ही एक फार्म भरवाती है उसका 150 व 250 रुपया अलग । जहाँ से चलेंगे वहाँ की सरकारें रेल तक छोड़ने का भाड़ा वसूल रही है।आज ही मुंबई में फंसे एक मजदूर जो डबरा तहसील के रहने वाले हैं ने मुझे फोन से यह जानकारी दी। एक बड़ा प्रभाव खुदरा व्यापारी के ऊपर पडना है जिससे वस्तुतः कई करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इनमें भी ग्रामीण और कस्बाई ज्यादा प्रभावित होंगे। जिस योजना पूर्वक सरकार ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और होम डिलीवरी की शुरुआत की है उसका प्रभाव शहरी खुदरा और थोक व्यापारियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है ।क्योंकि मॉल या विदेशी कंपनी वाले सीधे उत्पादक से सामान लेते हैं जो उन्हें सस्ता पड़ता है।अब उनकी सीधी पहुंच फुटकर दुकानदारों तथा मध्य और उच्च मध्यमवर्ग तक हो गई है। उनका माल उपभोक्ता को तुलनात्मक रूप से सस्ता मिलता है। उनके पास वितरण के साधन भी बहुत ज्यादा हैं और फुटकर व्यापारी व आम ग्राहक इससे सीधे प्रभावित होंगे ।सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जाना आना, 6 फुट दूर गोले में, धूप फिर बारिश में खड़े रहकर कष्ट सहना व समय की बर्बादी अलग।

शहरी और महानगरी आम उपभोक्ता भी डिजिटलाइजेशन होने का प्रयास करेगा तथा होम डिलीवरी चाहेगा।उसे सस्ता और घर पर सामान मिलेगा। नगरों के छोटे दुकानदार भी होम डिलीवरी चाहेंगे। सीधा सस्ते दर पर दुकान में माल पहुंच जाएगा ना ऑटो, ना ठेला न जाने की परेशानी ना पास न परमिट । शहरी कर्मचारी उपभोक्ता भले ही उसकी क्षमता कम हो परंतु जीने की लाचारी के लिए उसे खरीदी करना ही होगी, परंतु ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सारे देश के अप्रवासी मजदूर जिनकी सरकार के अनुसार दर्ज संख्या 53 लाख हैपर वास्तव में जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है इस बार शहरों से कमा कर लाने के बजाय लुट पिटकर आये हैं।ये जब महानगरों से वापस लौटते थे तो अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारो के लिए भी बचाए हुए पैसे से यथाशक्ति सामान लेकर आते थे और अंततः यह सामान महानगरों के व्यापारी ही तो बेचते थे । इस बार एक मोटे अनुमान के

हिसाब से 4–5 हजार करोड़ की बिक्री की कमी महानगरों के थोक विक्रेताओं की हो गई है न खरीदने को पैसे हैं ना ले जाने का साधन हैं। जब खुद ही सैकड़ों किलोमीटर चलने को लाचार हैं तो कौन सामान खरीदेगा और कहां ले जाएगा ।यह मजदूर इतने पीड़ित हो चुके हैं कि अब जल्दी दिल्ली लौटने वाले नहप हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी के समर्थक राजनीतिक दानदाताओं के दबाव में केंद्र सरकार ने शहरों से बाहर निर्णय कर दिया कि महानगरों से बाहर के कारखाने खोल सकते हैं।आखिर महानगरों के बड़े–बड़े उद्योगपतियों से ही भाजपा की राजनीति चलती है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने यह सुझाव दिया है कि गरीबों की मदद के लिए 65 हजार करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना चाहिए ।उनका सुझाव ऊपरी तौर पर तो सभी को अच्छा लगेगा और जब गरीब का नाम जुड़ा है तो भले ही मन से ना सही परंतु शब्दों में सभी का समर्थन मिलेगा ।हालांकि इससे गरीबों के लिए वास्तव में कितनी मदद होगी और उसके क्या प्रभाव होंगे यह विचारणीय हैं ।मैं श्री राजन की शैक्षणिक योग्यता उनके प्रचलित अर्थशास्त्र के ज्ञान और उनकी नियत पर कोई संदेह नहप कर रहा हूं परंतु एक और भी जमीनी पक्ष है जो आमतौर पर बौद्धिक अर्थशास्त्र की .ष्टि से छूट जाता है ।मान लीजिए 65000 करोड रू. देश के 30 करोड़ गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वाले लोगों को बांट दिया जाए तो औसतन एक व्यक्ति को 2200 के आसपास मिल जाएगा ।यह पैसा किसी ना किसी रूप में बाजार में आएगा।इतनी राशि से मान लें कि एक गरीबी रेखा के नीचे वाले का 1 माह का खर्च निकल जाएगा तो क्या 1 माह के बाद संकट नहप रहेगा। दूसरे 2 –3 हजार की पूंजी से कोई व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा नहप हो सकता है ।

मैं मान सकता हूं कि इस 65000 करोड का 30: दुकानदारों को मुनाफे के रूप में मिल सकता है यानी लगभग 10 से 15 हजार करोड रुपया देश के दो से तीन करोड़ व्यापारियों के पास पहुंचेगा यानी औसतन एक व्यापारी के पास 5–6 हजार रु का लाभ,तो क्या इतनी राशि से फुटकर व्यापारी का जीवन चल जाएगा ।हां यह हो सकता है कि, अगर गरीबों को मदद भारत सरकार ने एक साल बाद चुनाव के पहले दी तो सरकार को चुनाव जीतने में जरूर सहयोग मिल जाएगा ।अगर चुनाव के पहले 5–5 हजार रूपये भी लोगों के खाते में पहुंच गए तो सरकार आराम से 15 से 20: वोट ज्यादा पाएगी । गरीब दो–तीन माह के बाद फिर ज्यों का त्यों गरीब हो जाएगा, पर सरकार के 5 वर्ष पक्के हो जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े लोगों को जो सुविधाएं दे रही है वह आर्थिक अपराध भी छुप जाएंगे। 68500 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी जैसे लोगों का पैसा राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल दिया है ।श्री राहुल गांधी ने इस सवाल को तकनीकी रूप से नहप छेड़ा जिसका लाभ सरकार ने उठा लिया ।श्री राहुल ने इसे कर्ज माफी कहा जब की अर्थशास्त्र की तकनीकी भाषा में कर्ज माफी के लिए वेवर और बट्टे खाते के लिए राइट ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाता है। बट्टे खाते में भले ही सीधी माफी ना हो वसूली के प्रयास लायक माना जाता हो परंतु कुल मिलाकर यह कर्जमाफी की ओर जाने वाला मार्ग । लॉकडाउन के खबरों के बीच एक बड़ी खबर दब गई कि भारत सरकार ने देश के छः हवाई अड्डों को निजी हाथों में देने का निर्णय कर लिया तथा 3 माह में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ।इसके लिए कई तर्क दिए दिए हैं कि इस कदम से हवाई यात्रा का समय और एयरलाइंस की लागत कम हो जाएगी। यात्रा का समय तो विमानों की गति तय करती है ना कि मालिक। बल्कि अनुभव यह है कि निजी विमान कंपनियां एक विमान को पांच–पांच रूट पर चलाती हैं जिससे विमान घंटों लेट होते हैं ।लागत खर्च इससे कम कैसे हो जाएगा, बल्कि यात्रा की अवधि व खर्च बढ़ेगा।यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी सुविधाएं कम होंगी और लूट बढेगी ।जनता का बैंकों का पैसा विमान कंपनियां डुबायेंगी । क्या हम लोग कुछ ही माह पहले श्री गोयल के जेट एयरवेज की घटना को भूल गए? इसी निजी कंपनी ने कुल मिलाकर देश की गरीब जनता का बैंक ऋण और अन्य प्रकार से लगभग 20000 करोड रुपए बर्बाद कर दिया ।

फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग का अर्थ क्या है यह भी जान लेना चाहिए इस समय जब सारी दुनिया में कोरोना से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हैं लोग कह रहे हैं कि अमेरिका बर्बाद हो गया तब अमेरिका के कैलिफोर्निया की एप्पल कंपनी ने 3 माह में बिक्री कुछ कम होने के बाद भी मुनाफा 1: ज्यादा कमाया है और 3 माह में रू 436000 करोड़ यानी औसतन 1 माह में रू 113000 करोड +का मुनाफा कमाया है ।गूगल और फेसबुक ने भी इसी बीच लाखों करोड़ रु का मुनाफा कमाया है। फेसबुक ने तो मुकेश अंबानी के जिओ के 10: शेयर खरीद लिए हैं ।जब दुनिया की सरकारें और लोग घाटे में हैं जाते हैं तो दुनिया का पूंजीवाद तरक्की करता है।

मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि –

1. कोरोना संकट का इस्तेमाल निजीकरण के लिए ना करें बल्कि शिक्षा चिकित्सा यातायात का निजीकरण समाप्त करें ताकि आम लोगों को सस्ती सेवा मिल सकें ।

2. समूचे देश में केंद्र और राज्य सरकारें इस संकट का इस्तेमाल राष्ट्र के स्थाई विकास के लिए करें ।समूचे देश में नहरों का जाल बिछाने पर पैसा खर्च करें ताकि आगामी बारिश के दौरान देश बाढ़ तथा सूखे से मुक्त हो सके। आगामी दो माह केवल राष्ट्रीय बाढ़ सूखा मुक्ति नहर योजना पर पैसा खर्च किया जाए ।इससे मनरेगा जैसी योजनाओं के पैसे का सदुपयोग होगा और जमीनी स्तर पर नीचे के भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी।

भारत सरकार पंचायत स्तर पर विकेन्द्री.त ,खाद्य, प्रसंस्करण, .षि आधारित, उद्योग कोल्ड ड्रिंक पेय जल आदि उद्योग लगाए तो 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है।पलायन थम जाएगा।कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियां हवाई व बड़े लोगों तक सिमट जाएंगी।चीन,अमेरिका आदि से उपभोक्ता वस्तुओं को आयात की जरूरत नहप होगी।और आजादी के महात्मा गांधी और अन्य नायकों के सपने पूरे हो सकेंगे।

(विचार–मंथन)

उद्योगों को राहत

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूती के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई, कुटीर उद्योगों और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छह नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसमई सेक्टर के लिए चार हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी जिससे दो लाख कंपनियों को फायदा होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग मिलकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री आ. टोमैटिक लोन का प्रवाधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसकी समयसीमा भी चार वर्ष की होगी। पहले एक वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर, 2020 से स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख यूनिट बिजनस ऐक्टविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं और उनके यहां नौकरियां बचाई जा सकती हैं।

एमएसएमई क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए राहत पहुंचाए जाने के संकेत पहले से मिलने लगे थे। अब जो ऐलान किए गए हैं, वह छोटे उद्योगों और करोड़ों कामगारों के लिए उम्मीद की किसी किरण से कम नहीं है। पिछले पचास दिन से जारी लॉक. डाउन ने न सिर्फ उद्योगों, बल्कि करोड़ों कामगारों को बेहाल कर दिया है। इसी का नतीजा है कि देश

में लाखों कामगारों को अपने घरों को लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल, छोटे उद्योग ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और देश के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सामान के उत्पादन से लेकर बड़े उद्योगों तक के लिए कच्चा–पक्का माल छोटे और मझोले उद्योग ही तैयार करते हैं। ऐसे में अब इस क्षेत्र की और अनदेखी से संकट और गहरा सकता है। फिर से काम चालू करने के लिए उद्योगों के सामने नगदी और मांग जैसी कई तरह की मुश्किलें हैं। पहली जरूरत तो नगदी की है। नगदी होगी तो कच्चा माल खरीदेंगे और उत्पादन शुरू हो पाएगा। नगदी के अभाव में उद्यमी कर्मचारियों को वेतन देने, अपनी इकाई के बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जगह का किराया, बैंक से लिए कर्ज की किस्त और उसका ब्याज चुकाने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

ऐसे में सवाल यह है कि लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो एकदम से मांग, उत्पादन और बिक्री का चक्र चलने वाला नहीं। तब अगले छह–आठ महीने इस तरह के खर्च कहां से किए जाएंगे, यही बड़ा संकट है। जिन छोटे उद्योगों को काम शुरू करने की इजाजत मिल भी गई है, उनमें भी काम इसलिए नहीं शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम करने वाले अपने घरों को लौट गए हैं। लॉकडाउन के कारण जिस तरह से उद्योगों का पहिया ठहरा और उत्पादन रुक गया, उसे फिर से ढर्रे पर लाने में वक्त लगना लाजिमी है। दूसरी ओर अब बाजार में सबसे बड़ा संकट मांग का भी बना हुआ है। आबादी का बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वह जरूरत भर का सामान मुश्किल से खरीद पा रहा है। मध्यमवर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें तो पूरी कर रहा है, लेकिन जो कुछ बचा–खुचा पैसा है, उसे संकट के लिए बचा कर रखने में भलाई समझ रहा है। ऐसे में सवाल है कि मांग कैसे बने बाजार में। अगर मांग कमजोर पड़ी रही तो छोटे उद्योग कितना ही उत्पादन कर लें, माल बिकेगा नहीं और इससे नया संकट खड़ा होने लगेगा। छोटे उद्योगों के लिए हालांकि रिजर्व बैंक ने कई तरह की सहूलियतों का एलान करते हुए बैंकों को निर्देश दिया था कि वे उद्यमियों को बिना किसी दिक्कत के कर्ज दें और बकाए के लिए उन पर दबाव न बनाएं। लेकिन बैंकों के सामने अपनी मजबूरियां हैं। आंख मूंद कर कर्ज देने से बैंक बचना चाहते हैं। बैंकों को डर है कि अगर कर्ज वापसी नहीं हुई तो क्या होगा। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पहले से ही नगदी संकट का सामना कर रही हैं, इसलिए वे भी छोटे उद्योगों को कर्ज बांटने का जोखिम लेने से बच रही हैं। जाहिर है, संकट अनुमान से ज्यादा गहरा है। लेकिन मदद के लिए सरकार की भी अपनी व्यावहारिक सीमाएं हो सकती हैं। ऐसे में रास्ता कैसे निकले, यह बड़ा सवाल है। सरकार और उद्योग जगत को मिल–बैठ कर इस संकट का समाधान खोजना होगा।

(विचार–मनन)

दूसरे की गलती

एक बार गुरु श्यामानंद ने अपने चार शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया। पढ़ाने के बाद वह अपने शिष्यों से बोले, 'अब तुम चारों इस पाठ का बार–बार अध्ययन कर इसे याद करो। इस बीच यह ध्यान रखना कि तुम में से कोई बोले नहीं। थोड़ी देर बाद मैं तुमसे इस पाठ के बारे में बात करूंगा।' यह कहकर श्यामानंद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद चारों शिष्य अलग–अलग बैठकर पाठ का अध्ययन करने लगे।

अचानक बादल घिर आए और वर्षा की संभावना बन गई। यह देखकर एक शिष्य बोला, 'लगता है, तेज बारिश होगी।' यह सुनकर दूसरे ने कहा, 'तु? हें बोलना नहीं चाहिए था।' तभी तीसरा बोला, 'तुम लोगों ने बोलकर गुरुजी की आज्ञा भंग कर दी है।' चौथा शिष्य चुपचाप पाठ पढ़ता रहा। इसी बीच श्यामानंद वहां आ गए। उन्हें देखकर पहला शिष्य बोला, 'गुरुजी, यह मौन नहीं रहा और बोलने लगा।' दूसरा शिष्य बोल पड़ा, 'तो तुम कौन सा मौन थे। तुम भी तो बोल पड़े थे।' तीसरे ने कहा, 'इन दोनों ने बोलकर आपकी आज्ञा भंग कर दी है।' यह सुनकर दोनों तपाक से बोले, 'तुम भी तो बोल ही पड़े थे।' मगर चौथा शिष्य अभी भी चुप था।

उसे देखकर गुरुजी बोले, 'तुम में से केवल इसने ही मेरी आज्ञा मानी। यह निश्चय ही आगे चलकर बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य करेगा क्योंकि इसके भीतर

पर्याप्त धैर्य और एकाग्रता है। यह किसी के बहकावे में नहीं आता न ही किसी क्षणिक हलचल से विचलित होता है। तुम तीनों के भविष्य को लेकर मुझे शंका है क्योंकि तुम तीनों एक दूसरे का दोष निकालने के कारण स्वयं भी गलती कर बैठे। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। वे दूसरे को उसकी गलती बताने के चक्कर में स्वयं भी गलती कर बैठते हैं और फिर स्वयं कब गलत मार्ग पर चलने लगते हैं, इसका उन्हें आभास तक नहीं होता।' यह सुनकर तीनों शिष्यों का सिर शर्म से झुक गया।

प्रसंगतः जज का फैसला

पी. डब्ल्यू रिमथ अमेरिका के मशहूर जज थे। एक बार वह अदालत से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी से टकरा कर एक व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल भीड़ इकट्ठा हो गई और जैसा कि होता है, सभी लोग कार चालक को बुरा-भला कहने लगे। लेकिन लोगों को जब पता चला कि कार चालक कोई और नहीं जाने-माने न्यायाधीश रिमथ हैं, तो लोग घायल व्यक्ति को ही दोषी ठहराने लगे। रिमथ ने कहा, 'इस समय कौन दोषी है, इसका फैसला आप लोग नहीं कर सकते। इसका निर्णय तो अदालत करेगी। इस समय तो इस शख्स को इलाज की जरूरत है।' जज साहब लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए और उसकी मरहम पट्टी कराई। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में तैनात पुलिस से कहा, 'यह मेरी गाड़ी से घायल हुआ है, मेरे खिलाफ इसका केस दर्ज किया जाए।' पहले तो पुलिस वालों ने आनाकानी की, लेकिन रिमथ के दबाव पर केस दर्ज हो गया। दूसरे दिन पुलिस ने उनके सामने यह केस पेश किया। इससे कुछ दिनों पहले रिमथ ने इसी तरह के हादसे में एक व्यक्ति को 15 दिन की कैद या 15 डॉलर जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसी फैसले को नजीर मान कर उन्होंने अपने को वही सजा सुना दी, फिर पुलिस से कहा, 'मुझे जेल ले चलो।' पुलिस वाले उच्चाधिकारियों के आदेश के बिना जज साहब को जेल कैसे ले जाते! उन्होंने इसकी सूचना मुख्य न्यायाधीश को दी। मुख्य न्यायाधीश कुछ देर बाद रिमथ की अदालत में पहुंचे और कहा, 'हमें आप के निर्णय पर गर्व है। यदि सभी जज आप की तरह इंसाफ करने लगे तो लोगों का इंसाफ पर भरोसा और मजबूत होगा। आप ने अपना फैसला सुना दिया। अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए।' मुख्य न्यायाधीश ने कैद की जगह 15 डॉलर का जुर्माना स्वयं देकर रिमथ को बरी कराया। रिमथ ने कहा, 'इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए।' यह कह कर उन्होंने 15 डॉलर चीफजस्टिस को लौटा दिये।

दैनिक पंचांग

15 मई 2020 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	वृष में	वृष	5.21 बजे से
चंद्र	कुंभ में	मिथुन	7.19 बजे से
मंगल	कुंभ में	कर्क	9.32 बजे से
बुध	वृष में	सिंह	11.48 बजे से
गुरु	मकर में	कन्या	14.00 बजे से
शुक्र	वृष में	तुला	16.11 बजे से
शनि	मकर में	वृश्चिक	18.26 ब.से
राहु	मिथुन में	धनु	20.42 बजे से
केतु	धनु में	मकर	22.47 बजे से
		कुंभ	00.33 बजे से
		मीन	2.06 बजे से
		मेष	3.37 बजे से

राहुकाल 10.30 से 12.00 बजे तक

शुक्रवार 2020 वर्ष का 136 वां दिन
दिशाशूल पश्चिम **ऋतु** ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2077 **शक संवत्** 1942
मास ज्येष्ठ (दक्षिण भारत में वैशाख)
पक्ष कृष्ण
तिथि अष्टमी 8.23 बजे को समाप्त।
नक्षत्र धनिष्ठा 8.30 बजे को समाप्त।
योग इन्द्र 01.48 बजे रात्र को समाप्त।
करण कौलव 8.23 बजे तदनन्तर तैतिल 21.20 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 21.9 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 18° 55'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1870519
जूलियन दिन 2458984.5
कलियुग संवत् 5121
कल्पारंभ संवत् 1972949121
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885121
वीरनिर्वाण संवत् 2546
हिजरी सन् 1441
महीना रमजान **तारीख** 21
विशेष राम भक्त केवट जयन्ती।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
चर	05.55 से	07.23 बजे तक	रोग	05.38 से	07.1 बजे तक
लाभ	07.23 से	08.51 बजे तक	काल	07.11 से	08.43 बजे तक
अमृत	08.51 से	10.19 बजे तक	लाभ	08.43 से	10.15 बजे तक
काल	10.19 से	11.47 बजे तक	उद्वेग	10.15 से	11.47 बजे तक
शुभ	11.47 से	01.15 बजे तक	शुभ	11.47 से	01.19 बजे तक
रोग	01.15 से	02.43 बजे तक	अमृत	01.19 से	02.51 बजे तक
उद्वेग	02.43 से	04.10 बजे तक	चर	02.51 से	04.23 बजे तक
चर	04.10 से	05.38 बजे तक	रोग	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

आज का कार्टून।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे श्रमिकों को बस ने यूपी में रौंदा,6 की मौत

मुजफ्फरनगर (ईएमएस)। लॉकडाउन के चलते रोजगारविहीन मजदूर अब पलायन को अब पैदल ही अपने घरों की ओर चल रहे हैं। ऐसे में यूपी के मुजफ्फरनगर–सहारनपुर हाइवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। पैदल अपने गांव जा रहे 6 मजदूरों को एक तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। सभी मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। घटना घलौली चेक पोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास की है। बुधवार देर रात जब मजदूर पंजाब से पैदल अपने घर बिहार जा रहे थे, तभी बस ने उन्हें कुचल दिया। आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, कुल 10 मजदूर पंजाब से बिहार लौट रहे थे। बस के नीचे आने से इनमें से 6 की मौत हो गई जबकि बाकियों की हालत गंभीर है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा रोडवेज बस से हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, हादसा बुधवार रात 11:45 बजे हुआ। पंजाब में काम करने वाले मजदूर देर रात को पैदल सहारनपुर से होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कोई रो. डवेज बस उन्हें कुचलते हुए फरार हो गई।

यह हादसा रोडवेज की बस से हुआ और वह आगरा के ताज डिपो की है। पुलिस ने रात में ही सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में मारे गए लोग बिहार के गोपालगंज के बताए जा रहे हैं।

इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मज. दूरों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ था। यहां रेल की पटरियों पर आराम कर रहे 16 प्रवासी मज. दूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई थी।

मजदूर पैदल ही महाराष्ट्र के जालना से मध्यप्रदेश जा रहे थे और रास्ते में थकने के कारण उनमें से 17 लोग ट्रेन की पटरियों पर आराम करने के लिए लेट गए जबकि तीन अन्य पास के खेत में विश्राम के लिए बैठ गए थे।

मऊ मे करोड़ों के वारे–न्यारे में कागजी संस्थाएं बनी आधार

हाल–ए– विकास खंड रतनपुर करोड़ों के अनियमित भुगतान का मामला

मऊ। विकास खंड रतनपुरा में महात्मागांध ी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के सामग्री मद से पदीय अधिकारो की आड़ मे बीडीयो के द्वारा खरीदी गई सामग्री के एवज में किए गए भुगतान की संस्थाओं को कागजी होने की खबर है। अधिकांश सस्थाएं ग्राम प्रधानों के द्वारा बनाई गई है या फिर उनके परिवार के नाम पर है। इन्ही संस्थाओं के सहारे ''बीडीओं'' ने ''मनरेगा'' के सामग्री मद से करोड़ों को ''वारा–न्यारा'' करने की साजिश रची थी। ''ईएमएस'' ने जैसे बीडीओं के द्व ारा किए गए अनियमित भुगतान की कलई खोली बिना काम कराए कागजी संस्थाओं के माध्यम से धन डकारने वाले ग्राम पंचायतों में कही मिटटी सोलिंग तो कही आरसीसी सड़क निर्माण तो कही खडंजा तो कही इंटरलाकिंग का हड़बड़ाहट मे काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान मानक को ताक पर रखकर केवल भुगतान को नियमानुसार साबित करने का प्रयास किया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार विकास खंड रतनपुरा में ग्राम पंचायतों के विकास के नाम पर वर्षो से कागजी संस्थाओं के माध्यम से सरकारी धनों की बंदरबांट जारी है। इन पूरे बंदरबांट में बीडीओ की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। मनरेगा की केवल बात करें तो इस योजना के तहत कराए गए कार्यो की तकनीकी जांच करने के बाद ही बीडीओं के द्वारा सामग्री मद से उस संस्था को धन आवंटित करने का काम किया जाता है जिसने निर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों का विक्रय किया हो। वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 29 गांवों मे मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो के एवज में सरकारी धनों का वितरण किया जाना था लेकिन इस बाध्यता को किनारे रख कर ग्राम प्रधानों के माध्यम से सामग्री आपूर्ति कर्ताओं को पटा कर बिना काम कराए अधिकांश ग्राम पंचायतों मे बीडीओं'' ने विकास का कागजी घोड़ा दौड़ाने की साजिश

सुपारी देकर पति ने कराई पत्नी की हत्या

गाजियाबाद (ईएमएस)। गाजियाबाद में महिला वकील की गोली मारकर हत्या किए जाने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि महिला के पति ने सुपारी देकर पत्नी की हत्या करवाई थी। फिलहाल मामले में भाड़े के हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यह मामला मंगलवार का है। हाजी सलीम ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी पत्नी दिव्या राणा के साथ कार से एक तीसरे शख्स को प्लॉट दिखाने ले जा रहा था और इसी दौरान तीसरे शख्स ने उसकी पत्नी को कार के अंदर ही गोली मार दी था और फरार हो गया था। पुलिस के लिए कार में हुए इस हत्याकांड को सुलझाना एक पहेली बन गया था। कारण ये था कि कार में तीन लोग थे। एक की हत्या हो गई, एक चश्मदीद गवाह और हत्या करने वाला फरार। लेकिन, बुधवार को पुलिस ने खुलासा किया कि महिला वकील दिव्या राणा की हत्या खुद उसके पति ने सुपारी देकर कराई थी पुलिस के मुताबिक दिव्या राणा अपने पति का बिजनेस हड़पना चाहती थी जिसको लेकर उसका पति बेहद परेशान था। हाजी सलीम को डर था कहीं उसकी पत्नी उसके सारे बिजनेस को अपनी तरफ न कर ले। इसी को लेकर सलीम ने अपनी पत्नी की सुपारी दे दी। पेशगी में 2 लाख रुपये दिए गए थे बाकी पैसा बाद में दिया जाना था। पुलिस ने हाजी सलीम को गिरफ्तार किया गया है। हत्या करने वाले दो बदमाश अभी फरार है।

लॉकडाउन में घूमने गया तो पिता व भाई ने ली जान

लखनऊ (ईएमएस)। लखनऊ में एक 19 वर्षीय युवक को उसके भाई और पिता ने पीट–पीटकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल, वह लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूमने गया था। इसके संबंध में इंस्पे. क्टर विभूति खंड श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि लोहिया अस्पताल से जानकारी मिली थी कि विभूति खंड के एक 19 वर्षीय युवक अनुपम ने आत्महत्या कर ली है और उसके शव को उसका परिवार ही अस्पताल लाया था। परिवार की बात को सच मानते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के सिर पर दो चोटों का खुलासा हुआ और पता चला कि युवक की मौत सिर पर लगी चोट से हुई है।

इस जानकारी पर पुलिस में अनुपम के पिता जसकरन और भाई अंकित से सख़्ती से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि अनुपम टाइल्स कारीगर था और लॉकडाउन के दौरान भी रात को अक्सर बाइक से घूमने निकल जाता था, जिसका पिता और भाई लगातार विरोध करते थे।

रविवार को भी खाना खाने के बाद रात 9 बजे अनुपम बाइक से घूमने चला गया था और देर रात लौटा तो पिता और भाई के साथ कहासुनी हो गई। जिस पर अनुपम ने गुस्से में अपना मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद पिता–पुत्र में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अनुपम की हत्या में उसके पिता जसकरन और भाई अंकित को गिरफ्तार करते हुए हत्या में इस्तेमाल डंडा बरामद कर लिया है।

दो मासूमों संग महिला की मौत का हुआ खुलासा:आपत्तिजनक फोटो के चलते महिला ने बच्चों संग की थी खुदकुशी.

अमेठी जिले के शिवरतन गंज थाना क्षेत्र के भवानीपुर गाँव में कुछ दिन पूर्व दो बच्चों सहित महिला के मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला को गांव का एक व्यक्ति परेशान किया करता था। जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने दो बच्चों समेत अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कारवाई में जुट गई है। बता दे कुछ दिन पूर्व शिवरतन गंज थाना क्षेत्र के भवानी पुर गाँव में एक महिला तबस्सुम बानो और उसके बच्चे नुरू (8 वर्ष)और शोयब (5 वर्ष) की घर में संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई थी।पुलिस की जांच में पता चला कि महिला और दोनों बच्चों की मौत आग लगने से हुई है।और महिला का पति गुजरात के बड़ोदा में मजदूरी करता है.थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना सन्तोष कुमार सिंह ने बताया कि 12 मई को मृतक महिला का पति थाने पहुँचा और तहरीर दी कि

उसी के गाँव का एक व्यक्ति राम नायक पुत्र त्रिभुवन यादव उनकी बीबी को काफी परेशान किया करता था।आरोपी युवक ने महिला की निजी तस्वीरें खींच ली थी जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने दो बच्चों समेत जान दे दी। पुलिस की छानबीन में आरोपी युवक के मोबाइल फोन से महिला की कुछ निजी तस्वीरें मिली है।वही अब पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कारवाई में जुट गई है।

जिला जज ने कवरन्टीन सेंटरों किया निरीक्षण

सीतापुर(ईएमएस)। उच्च न्यायालय इला. हाबाद व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन में जिला सीतापुर न्यायाधीश कुलदीप कुमार के निदेशानुसार जनपद सीतापुर में स्थापित कवरन्टीन सेंटरो का निरीक्षण सुनील कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर द्वारा किया गया जिसमें पाया गया कि उत्सव गेस्ट हाउस लोहार बाग में कुल 79 व्यक्ति कवरन्टीन किया जा रहा है जिसमे 2 व्यक्ति जांच रिपोर्ट अभी शेष है जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी को गंतब्य स्थान भेज जाएगा उत्सव गेस्ट हाउस कवरन्टीन सेंटर में डॉ0 राकेश कुमार होम्योपैथिक डॉ0 संजय कुमार एलोपैथिक व लेखपाल गौरव श्रीवास्तव आदि कर्मचारी मौजूद मिले साथ ही कवरन्टीन सेंटर पर साफ सफाई के साथ साथ कवरन्टीन सभी व्यक्तियों के भोजन सामग्री आदि का निरीक्षण किया गया।

जिले में आयकर और व्यापार कर भरने वाले भी ले रहे सरकारी अनाज मुफ्त

अमेठी (ईएमएस)। जिले में आयकर और व्यापार कर भरने वाले भी सरकारी अनाज मुफ्त में लेते हैं। जिससे सरकारी खजाने को हर महीने लाखों का चूना लगता है। जबकि अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने अपात्रों को सरकारी राशन न लेने का आदेश जारी कर रखा है।लेकिन जिलाधिकारी के आदेश का असर अपात्रों पर नहीं है। इस पर केंदीय मंत्री स्मृति ईरानी के अपर सचिव विजय गुप्ता ने कहा कि गरीबों के हक पर अमीरों का अधि ाकार नहीं है। जबकि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि मोदी और योगी की सरकार में हेराफेरी करने वाला नहीं बचेगा।इनकी सरकार आधार से अमीरों की धड़पकड़ करने की तैयारी में जुटी है।बाकी पूर्ति विभाग के गोरखधंधे पर भी सरकार की पैनी नजर है।जिले में सवा चार लाख कार्डध ाारक है।लेकिन इसमें तीस फीसद से ज्यादा अपात्र राशन कार्ड बने हैं।राशन कार्ड की फीडिंग पूर्ति विभाग खुद करता है।फीडिंग करने और कराने वालों की बकायदा रेट सूची है।जिससे अपात्रों के राशन कार्ड बने हैं। कोटेदारों से मुफ्त में सरकारी राशन लेने वालों में सरकारी नौकरी,ईट भट्ठा मालिक,सफारी और लग्जरी के मालिक,टैक्टर ट्क,ठेकेदार जमीदार,दूध व्यापारी,रिटायर कर्मचारी आदि है।

अमेठी के एक ग्राम पंचायत अधिकारी ने बताया कि केशवनगर ,सरवनपुर खेरौना, रायपुरफुलवारी महमूद पुर आदि सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी शिक्षक,शराब व्यापारी, भट्ठा मालिक,महगी महंगी गाडियों के मालिक मुफ्त में सरकारी राशन लेते हैं। राजकुमार सिंह कोटेदार ने बताया कि हर कोटेदार के यहाँ तीस फीसद से ज्यादा अपात्र राशन कार्ड बने हैं। लेकिन कोटेदार जानते हुए भी मजबूर है। कोरोना की पूर्णबंदी में शुकवार को चौथे चरण का सरकारी राशन का वितरण शुरू होगा। जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को खाने पीने की किल्लत नहीं है। इसमें 70737 कार्ड धारकों को चौथी बार मुफ्त में राशन मिलेगा। जिला पूर्ति अधि ाकारी संजय कुमार ने बताया कि अमेठी के तेरह ब्लाकों में करीब सवा चार लाख कार्डध ाारक है। इसमें 70737 कार्ड धारक अति गरीब है। जिससे इनको महीने में दो बार मुफ्त में सरकारी राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र गृहस्थी योजना में एक यूनिट पर पांच किलो सरकारी राशन मिलता है। लेकिन इस योजना में तीन किलो गेंहू दो रुपए के हिसाब से बाकी दो किलो चावल तीन रुपए के हिसाब से मिलता है। लेकिन पात्र गृहस्थी योजना में एक यूनिट पर पांच किलो निशुल्क सरकारी चावल भी बट रहा है।मगर पात्र गृहस्थी योजना में निशुल्क सरकारी चावल केवल पूर्ण बंदी तक के लिए है। इसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड धारको और रजिस्टर श्रमिकों को भी मुफ्त में सरकारी राशन मिल रहा है।

विपरण कार्यालय के सरकारी राशन उठान के आकड़ों में केवल अपैल महीने के अन्त्योदय योजना में मुफ्त बटने वाला गेंहू 1407.560 मीटिंग टन ,मुफ्त चावल 1055.670 मीटिंग टन और इसी योजना में अतिरिक्त मुफ्त चावल 1154.226 मीटिंग टन 70737 कार्ड धारकों के नाम था।इसके बाद पात्र गृहस्थी योजना में 327620 कार्ड धारकों के लिए 5762.865 मीटिंग चावल मुफ्त बटने के लिए था। लेकिन पात्र गृहस्थी योजना में गेंहू 3497.421 मीटिंग टन दो रुपए किलो और 2331.614 मीटिंग टन चावल तीन रुपए किलो के हिसाब से आया था। सरकार ने राशन के साथ एक किलो दाल भी देने का ऐलान किया था। लेकिन पूर्ण बंदी में अब तक किसी को दाल मिली नहीं है।

मजदूरों को ले जा रही डीसीएम पलटी, 7 घायल

मसौली बाराबंकी (ईएमएस)। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को मुंबई से सिद्धार्थ नगर ले जा रही डीसीएम वाहन गोण्डा– बहराईच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुड़वा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें सवार लगभग 67 मजदूरो में 7 मजदूर आंशिक रूप से घायल हो गये जिन्हें सीएचसी रामनगर में भर्ती करवाया गया। गोण्डा– बहराइच हाइवे पर स्थित कुड़वा गांव के निकट गुरुवार की भोर करीब तीन बजे एक डीसीएम नम्बर एम एच 48 बी एम 1126 जो मुम्बई से प्रवासी मजदूरों को लेकर सिद्धार्थनगर जा रही थी डीसीएम चालक के नींद आ जाने से अनियन्त्रित होकर खाई में पलट गयी डीसीएम में सवार करीब 67 प्रवासी मजदूरों की चीख पुकार सुन पास के गांव के तमाम लोग पहुंच गये और आनन फानन में मसौली पुलिस को सुचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र प्रताप रावत सहित सहयोगी पुलिसकर्मियों ने डीसीएम में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जिसमे 7 मजदूर आंशिक रूप से घायल हो गये थे जिन्हें सीएचसी रामनगर में भर्ती कराया गया बाकी अन्य मजदूरों को दूसरे वाहनों पर सवार कर रवाना कर दिया गया। हादसे में 40 वर्षीय भुलाई पुत्र होली, 48 वर्षीय राम बहादुर पुत्र रामजी, 25 वर्षीय सोनू पुत्र बांके निवासी आदमपुर थाना बेगमगंज गोण्डा, 45 वर्षीय पुजारी पुत्र तिलकराम गोपीपुर थाना तरबगंज गोण्डा व 30 वर्षीय राजेश पुत्र बेचन गोडारी थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर को आंशिक चोटे आयी हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है।

मथुरा में हुई 21 लाख बैंक डकैती का हुआ खुलासा

लखनऊ (ईएमएस)। कृष्णनगरी मथुरा में तीन दिन पहले हुई 21 लाख की बैंक डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूट के 12 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईजी रेंज आगरा बी सतीश गणेश ने बताया कि 3 दिन पहले मथुरा के आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में हुई डकैती के सुराग पहले दिन ही मिलने लगे थे। बैंक के आसपास के अपराधी किस्म के युवकों पर पुलिस को शक हुआ था क्योंकि लॉकडाउन के चलते बाहर के लोगों की बहुत ज्यादा आमद इस इलाके में नहीं थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि इलाके के एक पुराने अपराधी सम्राट को उस दिन बैंक के आसपास देखा गया था। जानकारी पर पुलिस ने सम्राट के घर पर छापा मारा तो वह घर पर नहीं मिला। इसके बाद सम्राट के पिता और भाई की बातों से भी अंदेशा हो गया कि सम्राट ने कुछ गड़बड़ की है। आईजी रेंज ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी नई उम्र के हैं और दिन भर मोबाईल पर व्यस्त रहते हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी संदिग्ध ों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई। पता चला कि आसपास के ही राहुल, गौतम, अंकित ,अवनीत, परमिंदर का सम्राट के साथ उठना बैठना है। इन सभी युवकों के अवैध असलहों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरों को देखा जा सकता था। इसके बाद पुलिस ने रज्जो के घर छापा मारा तो वह नहीं मिली। इसके काफी मशक्कत के बाद रज्जो गिरफ्तार हुई जिसके पास से डकैती के 12 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। फ़िलहाल पुलिस डकैती के मास्टरमाइंड सम्राट और परमिंदर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

ट्रेन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को बादशाही अखाड़ा पिला रहा है जल जीरा

बस्ती (ईएमएस)। कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉक डाउन में लगातार जन सेवा में जुटा बादशाही अखाडा बेजुबानों की सेवा के बाद बाहर से रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे श्रमिकों को शिकंजी, जलजीरा पिला कर लोगो की प्यास बुझा रहा है।

पिछले चार दिनों से नीबू पानी पिला रहे बादशाही अखाडा की स्टाल पर गुरूवार को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार, सूचना अधिकारी,एसडीएम सदर ने भी पहुंच कर स्वयंसेवको का उत्साह बढाते हुए नीबू पानी पिया।

बादशाही अखाडा के कुलवेन्द्र सिंह मज. हबी ने बताया कि लगातार ट्रेनों के आने से बादशाही अखाडा के स्वयं सेवको द्वारा लोगो आसानी से शिकंजी पिलाया जा सके इसके लिएं डी0एस0 ग्रुप कैच मसाला के मार्केटिंग मै. नेजर हर्षित मिश्रा द्वारा बादशाही अखाडा को जलजीरा के पैकेट उपलब्ध कराते हुए कहा कि इस जन सहयोग के लिए हम सदैव खडे रहेगें।

एचआईवी, क्षय रोगियों के घरों तक पहुंचा रहे हैं दवा,मास्क,सेनेटाइजर

बस्ती (ईएमएस)। प्रवासी श्रमिकों के बीच कार्य करने वाले ग्रामीण विकास सेवा समिति की ओर से मास्क निर्माण के साथ ही मास्क और सेनेटाइजर

जनपद के 10 चयनित विकास खण्डों के 100 ग्राम पंचायतों के टी.बी., पीएल एचआईवी, ट्रक ड्राइबरों, गर्भवती महिलाओं में वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही क्षय रोगियों और पीएल एचआईवी रोगियों को औषधि उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुये समिति के सचिव रामल. लित यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी लखनऊ के लिंक वर्कर स्कीम के तहत पिछले 7 वर्षो से एचआईवी एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। अब कोरोना संकट काल में चिन्हित परिवारों में समिति की कार्यकर्ताओं की ओर से जनपद के 100 ग्राम पंचायतों में मास्क और सेनेटाइजर का वितरण किया जा रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सुरत बस की लाईन लगी

17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण पूर्ण हो रहा है और उसके बाद गुजरात में रोडवेज बस में लोग अपने गाँव जा रहे हैं गुजरात सरकार ने गुजरात के अन्य शहरों में फँसे लोगों को उसके स्थान पर पहुचने के लिये यह व्यवस्था किया हैं

प्रवासी मजदूरों ने दहेज में भारी हंगामा और चक्काजाम किया

भरुचं। लॉकडाउन के चलते गुजरात में फंसे प्रवासी मजदूरों को धैर्य अब जवाब देने लगा है। हांलाकि सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें चला रही है। ले. किन जिन प्रवासी मजदूरों को अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, वह आक्रामक होते जा रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द उन्हें घर भेजने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भरुच के दहेज में ऐसे ही प्रवासी श्रमिकों ने गृहराज्य भेजने की मांग को लेकर जबर्दस्त हंगामा कियाद्य आक्रोशित श्रमिकों ने दहेज के जोलवा के निकट चक्काजाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस श्रमिकों को समझाने का प्रयास कर रही हैद्य दूसरी ओर वलसाड के वापी में श्रमिकों के हंगामा करने की खबर है।

वापी के मोराई स्थित वेलस्पन कंपनी में आज मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। कंपनी के कामगारों ने वेतन नहीं मिलने पर बवाल कियाद्य फिलहाल कंपनी संचालक अपने कामगारों को समझाने का प्रयास कर रही है।

गुजरात से 3.95 लाख प्रवासी मजदूरों को विशेष श्रमिक ट्रेन से भेजा गया

अहमदाबाद । देशभर से अब तक 9.85 लाख प्रवासी मजदूरों को विशेष श्रमिक ट्रेन से उनके गृह राज्य भेजा गया है और इसमें सबसे अधिक ट्रेन गुजरात से चलाई गईं। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि राज्य में बीती मध्य रात्रि तक 302 ट्रेनें चलाई गई और उनके जरिए अब तक 3.95 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है। जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 204, बिहार के लिए 34, उडीसा के लिए 30, मध्य प्रदेश के लिए 20, झारखंड के लिए 8, छत्तीसगढ़ के लिए 3 और उत्तर खंड के लिए 2 ट्रेनें रवाना की गईं। आज और 47 ट्रेनें 75200 प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना होंगी। प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे अधिक ट्रेनें गुजरात से चलाई जा रही हैं। अश्विनी कुमार ने बताया कि किसानों का कपास के अच्छे दाम उपलब्ध हों और जल्द इसके खरीद शुरू हो, इसके लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय से पेशकश की हैद्य उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं और तूर की खरीदी की जा रही है। सिविल सप्लायर द्वारा 13722 मैट्रिक टन गेहूं और 3383 मैट्रिक टन तूर की खरीदी की गई है।

वहीं गुजकोमासोल द्वारा चना और राई की खरीदी गई है। जिसमें 24370 मैट्रिक टन चना और 3757 मैट्रिक टन राई खरीदी गई। मार्केट यार्ड में 40 क्विंटल की खरीदी की गई है। कुमार ने केन्द्रीय वित्त मंत्री के पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात एमएसएमई का गढ़ है और राज्य के ज्यादातर जिलों में एमएसएमई यूनिट कार्यरत हैं। केन्द्रीय पैकेज से गुजरात के लाखों यूनिट को लाभ मिलेगा और एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के उत्पादों की बिक्री और उपयोग केवल गुजरात तक सीमित नहीं है बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में किया जाता हैद्य राज्य के कई एमएसएमई से विदेशों में निर्यात की जाती है।

मजबूर हैं मजदूर हैं

नेताजी से परेशान हम मजदूर हैं

और ज्यादा क्या लिखूंगा फोटा में देखों हम मजबूर हैं

छोटे दुकानदारों को 2 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगी एक लाख की लोन : मुख्यमंत्री

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को आत्म निर्भर बनाने के ऐलान के बाद सभी राज्य अलग अलग प्रकार से आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे हैंद्य गुजरात सरकार ने भी राज्य के छोटे व्यापारियों को लोन मुहैया कराने का ऐलान किया है, ताकि वह आर्थिक से रूप से मजबूत हों। आत्म निर्भर गुजरात सहायता योजना के तहत राज्य के छोटे दुकानदारों को रु. 1 का लाख लोन 2 प्रतिशत के ब्याज पर मिलेगा। जबकि 6 फीसदी वार्षिक ब्याज का राज्य सरकार भुगतान करेगी। योजना के तहत पहले छह महीने मूल और ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं है यह ऋण सहकारी बैंक और जिला बैंकों से उपलब्ध होगा और इसके लिए किसी प्रकार की सिक्युरिटी देने की जरूरत नहीं है।

बैंक केवल आवेदन का आधार पर लोन पास करेगीद्य राज्य के 10 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी।

लॉकडाउन के बीच

महिला पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर जान दी

वडोदरा । लॉकडाउन के बीच वडोदरा के सावली में एक महिला कांस्टेबल के फांसी लगाकर जान देने की घटना से सनसनी फैल गईद्य आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला हैद्य पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू की हैद्य जानकारी के मुताबिक वडोदरा जिले की सावली में 22 वर्षीय शिल्पा विनोदसिंह दरबार बतौर पुलिस कांस्टेबल सेवारत थीद्य सावली की गोकुलवाटिका सोसायटी में किराए के मकान में रहनेवाली शिल्पा दरबार ने फांसी लगाकर जान दे दीद्य पड़ौसियों को घटना के बारे में सुबह पता चला और उन्हें तुरंत पुलिस को इत्तला कर दीद्य सूचना मिलते ही सावली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दियाद्य पुलिस को घटनास्थल से कोई स्यूसाइड नोट नहीं मिला।

सूरत से मजदूरों की वापसी के लिए रेल किराया वसूलने में भाजपा शामिल ?

सूरत । एक समाचार चैनल पर जारी समाचार के अनुसार गुजरात के सूरत से बिहार, उत्तरप्रदेश के अनेक क्षेत्रों में जाने वाले मजदूरों से 520 से लेकर 850 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यह वसूली कथित रूप से भाजपा कार्यालय में बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है।

न्यूज़ चैनल में जारी खबर के अनुसार सूरत में भाजपा यूथ विंग के सचिव भावेश टोपीवाला द्वारा लिस्ट बनाकर मजदूरों से वापसी के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसके एवज में मजदूरों को टिकट भी दी जा रही है। आमतौर पर टिकट रेलवे काउंटर पर मिलती है लेकिन जो वीडियो दिखाया गया है उसमें भाजपा के कार्यालय से टिकट देते हुए दिखाया जा रहा है। बताया गया है कि पटना के लिए 850 रुपए, प्रयागराज और लखनऊ के लिए 690 रुपए तथा वाराणसी के लिए 520 रुपए कथित रूप से प्रवासी मज. दूरों से टिकट के एवज में वसूले जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्हें डीएम से रेट कार्ड मिला है जिसके अनुसार वह वसूली कर रहे हैं।

16 – 16 यात्रियों के समूह बनाकर समूह के लीडर से पैसे एकत्र करवाए जा रहे हैं और वह पैसा कथित रूप से डीएम के पास पहुंचाया जाएगा ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है।

इस खबर का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कतार बना कर खड़े लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि जब सरकार ने प्रवासी मजदूरों की निःशुल्क वापसी की घोषणा की है तो फिर यह शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। क्या कुछ लोग इन बेबस मजदूरों की बेबसी का फायदा उठा कर वसूली का धंधा कर रहे हैं? इस मामले में भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इससे पहले भी गुजरात के सूरत मह. ानगरपालिका के एक पार्षद के भाई का वीडियो समाचार चैनल पर वायरल हुआ था जिसमें वे कथित रूप से श्रमिकों से अधिक मूल्य का किराया वसूल रहे थे। हालांकि बाद में पार्षद ने इस खबर का खंडन किया था और कहा था कि वीडियो पुराना है।

कांग्रेस ने जनता की श्वान से तुलना कर जनता का अपमान किया : भरत पंड्या

अहमदाबाद । गुजरात भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख द्वारा ट्वीटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या ने कहा कि कांग्रेस ने जनता की श्वान से तुलना कर जनता का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा ने अपने ट्वीटर पर पोस्ट किए वीडियो में कांग्रेस के विचार, आचार और विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने अपने 55 साल के कुशासन में जो भी किया वह प्रदर्शित किया है। कांग्रेस जनता को क्या समझती है? कैसे जानता है और किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करती है, उसका प्रतिबिंब इस वीडियो में दिखाई देता है। भरत पंड्या ने कहा कि कांग्रेस ने पब्लिक की डॉग के साथ तुलना कर पब्लिक का अपमान किया है। कांग्रेस पब्लिक को डॉग मानती है, जबकि भाजपा पब्लिक को गोड मानती है। भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है। भरत पंड्या ने कहा कि कांग्रेस के राजीव गांधी ने कहा था कि वह 1 रुपया जनता को भेजते है, लेकिन जनता के पास केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। अर्थात 85 प्रतिशत भ्रष्टाचार होता था।

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में प्रत्येक लाभार्थी के एकाउंट सीधे रुपए जमा होते हैं। बीते दिन ही कोरोना की महामारी में रु. 52606 करोड़ डीबीटी द्वारा करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश और जनता को लूटा था, जबकि भाजपा सरकारों में जनता का पैसा जनता तक पहुंच रह है। भेजे गए 100 प्रतिशत पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक एकाउंट में जमा होते हैं।

ट्रक में गाजर–मूली की तरह भरे मजदूर गुजरात से यूपी जा रहे थे, पुलिस ने 3 बेहोश बच्चों सहित 105 यात्री निकाले

वडोदरा। लॉकडाउन के चलते बेबस और लाचार मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है। गुजरात के आनंद में पुलिस एक कंटेनर ट्रक के अंदर 105 प्रवासी मजदूरों को देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने यह ट्रक लिंगदा गांव के पास चेकिंग के लिए रोका था। ट्रक में एक स्टिकर लगा था जिसमें लिखा था, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चिकित्सा आप. ूर्ति का लिए आपातकालीन ड्यूटी'। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कंटेनर से मिले प्रवासियों ने पुलिस को बताया कि उनसे उत्तर प्रदेश में उनके घर लौटने के लिए 3,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच शुल्क लिया गया था। ये सभी 105 प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और वे राजकोट से निकले थे। पुलिस ने उमरेथ तालुका में लिंगडा गांव के पास ट्रक चेकिंग के लिए रोका तो ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके कागज देखे गए तो पाया गया कि ड्राइवर के पास कोई वैध परमिट नहीं था और केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को दिए गए परमिट का दुरुपयोग कर रहा था।

आनंद जिले के पुलिस अध ीक्षक अजीत राजियान ने कहा कि जब ट्रक के अंदर देखा गया तो पुलिस हैरान हो गई। मिनी ट्रक यात्रियों से इतना खचाखच भरा था कि वे हिल भी नहीं सकते थे। तीन बच्चे पहले ही बेहोश हो चुके थे। सभी 105 यात्रियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। वहीं ट्रक चालक को भी गिरफ्तार करने से पहले उसकी कोविड–19 की जांच कराई गई। ड्राइवर अमृतलाल यादव भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आपदा प्रबंध ान अधिनियम की धोखाधड़ी और उल्लंघन के लिए अमृतलाल यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि मजदूरों ने इतनी जोखिम भरी यात्रा क्यों चुनी जबकि मजदूरों के लिए श्रमिक विशेष ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)